११

गोग्रास

अ.भा. कृषि गोसेवा संघ - गोपुरी - वर्धा.

अनुक्रमणिका

मुद्रक :

प्रकाशक :

प

अनुक्रमणिका

मुद्रक :

प्रकाशक :

प

वर्ष १ : अंक ११
११ सितंबर ७७

गोपुरी, वर्धा

वार्षिक शुल्क ६ रु.
प्रति अंक ५० पैसे

गोमाता के अनन्य उपासक संत विनोबाजी को
उनको ८३ वे जन्मदिन पर भक्तिपूर्वक प्रणाम

जयप्रकाश अमृत महोत्सव

अपील

यह हर्ष की बात है कि इस वर्ष विजया दशमी, तदनुसार २१ अक्तूबर १९७७ (अंग्रेजी कैलेन्डर के अनुसार ११ अक्तूबर) को लोकनायक जयप्रकाश अपने साधनामय जीवन के पचहत्तर वर्ष पूरे कर रहे हैं। जीवन भर उन्होंने राष्ट्र और मानवता के लिए निर्भय और निष्काम भाव से कार्य किया है। अभी भी वे एक नये भारत और नये विश्व के निर्माण के लिये जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए भी हमें दिशा निर्देश कर रहे हैं।

विविध पहलुओंका उनका व्यक्तिमत्व जनता के लिए श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक रहा है, क्योंकि वे मुक्त मानस और निश्छल हृदय से सत्य की खोज में निरंतर बढते रहे हैं। आज तक उन्होंने राष्ट्र को केवल दिया ही है, कुछ लिया नहीं। उनके जीवनपथ में राष्ट्र-भक्ति का उज्ज्वल दर्शन, पीडित और पददलित मानवता के लिए स्पंदन, लोकतंत्र और लोकशक्ति के संरक्षण के लिए जीवित आहुति देने का समर्पण और बापू के सपनों के निर्माण में लीन है। उनका जीवन सत्य का एक अविराम प्रयोग है। यही कारण है कि मार्क्सवाद से लोकतांत्रिक समाजवाद और फिर सर्वोदय से संपूर्ण क्रांति की ओर वे निर्भय होकर बढते रहे है। अभी हाल में उन्होंने युवाशक्ति एवं जनशक्ति को जिस प्रकार आवाहन कर राष्ट्र को एक चेतना दी है और उससे जनसाधारण का जो पुरुषार्थ प्रकट हुआ है उससे तानाशाही का अंत हुआ और हमने अपनी खोयी हुई स्वतंत्रता पाई। विराट् जन-आंदोलन को उन्होंने जिस प्रकार अहिंसक मोड देकर आदर्श उपस्थित किया है उसमें गांधी के साध्य और साधन दोनों का दर्शन होता है। संपूर्ण क्रांति के रूप में मोटे तौर पर बापू की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक क्रान्तियों को नई शक्ति दी गई और इससे गांधीजी

का अपूर्ण काम आगे बढानें में मदद मिली।

सन् १९४२ का विद्रोह, भारतीय समाजवाद का प्रवर्तन, भूदान-ग्रामदान-शान्ति सेना-सर्वोदय के लिए जीवनदान, चम्बल के वागियों का समर्पण, नागालैन्ड में शान्ति प्रयास, भारत-पाक मैत्री के लिये ठोस प्रयत्न, बंगला देश की मुक्ति के लिये जागतिक अभियान, बिहार दुर्भिक्ष निवारण में कारुणिक भूमिका, साम्प्रदायिक शान्ति के लिये अविराम प्रयास, गान्धीजी के ट्रस्टीशिप का प्रसारण, लोकचेतना एवं लोकमानस के जागरूक प्रहरी के रूप में वे सदा अविस्मरणीय रहेंगे।

जयप्रकाशजी का यह संदेश सुनने एवं समझने के लिए जसता आतुर है। इसके लिए हजारों भाई-बहनों को लगातार लंबे अर्से तक काम करने की आवश्यकता है। इसके पहले कदम के तौर पर ११ से २१ अक्तूबर तक देशभर मे फैले हुए गांव-गांव एवं नगर-नगर में जाकर संपूर्ण क्रांति का संदेश सुनाया जाय और अनुकूल स्थानों में लोकसमितियों की स्थापना की जाय। जो क्षेत्र एवं व्यक्ति इस आवाहन के लिए विशेष अनुकूल हो उनका सघन प्रशिक्षण कर ऐसे क्षेत्रों में संपूर्ण क्रांति के अगले कदम जनता उठावें। इन सब कामों को संपन्न करने के लिए जन एवं धन आवश्यक है। अतः जनता से हम अपील करते हैं कि वे जयप्रकाशजी के ७५ वर्ष पूर्ण करते शुभ अवसर पर अपना-अपना समयदान देवें एवं धन अर्पण करे, जिससे कि ७५ लाख रुपयों की थैली उन्हें भेंट की जा सकें। इस प्रकार जन एवं धन उपलब्ध होने से मानवीय मूल्यों पर आधारित समाजरचना बनने की दिशा में मानव आगे बढेगा।

जे. बी. कृपलानी
अध्यक्ष
जयप्रकाश अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समिति

अखिल भारत कृषि गोसेवा संमेलन समाचार

(३१ अगस्त और १ सितंबर १९७७)

ता. ३१ अगस्त और १ सितंब्र ७७ को अ० भा० कृषि-गोसेवा संघ द्वारा आयोजित गोसेवा संमेलन दिल्ली में हुआ। देशभर के कोने-कोने से प्रतिनिधि उसमें आये। स्वागताध्यक्ष लाला श्री. हंसराजजी गुप्त ने स्वागत किया। भारत के प्रधान-मंत्री श्री. मोरारजी भाई ने उसका उद्घाटन किया।

सर्व प्रथम श्री. रंगनाथजी दिवाकर अध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान के आशीर्वचनों से प्रथम दिन का कार्यारंभ हुआ। भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री. बरनालाजीने अध्यक्षता की।

भारत सरकार के कृषिमंत्री श्री. बरनालाजी ने प्रथम दिन के पहले सत्र की अध्यक्षता की। द्वितीय सत्र का दोपहर का संमेलन राज्यरक्षामंत्री प्रो. शेर सिंहजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दूसरे दिन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष श्री तुलसीदासभाई विश्राम, उपाध्यक्ष, अ० भा० कृषि गोसेवा संघ थे और आखिरी सत्र का अध्यक्षस्थान गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री. श्रीमन्नारायणजी ने विभूषित किया। भारत के रक्षामंत्री श्री. जगजीवनरामजी ने इस संमेलन का समापन भाषण किया।

प्रधानमंत्री और कृषिमंत्रीजी ने संमेलन के सन्मुख जो विचार अपने भाषण में प्रकट किये वे इसी अंक में अन्यत्र दिये हैं। संमेलन में पारित कुछ प्रस्तावों का जिक्र इसी अंक में आया है।

गोवध बंदी के समर्थन में आचार्य काकासाहेब कालेलकर, आचार्य जे. बी. कृपलानीजी एव लोकनायक जयप्रकाशजी के संदेश प्राप्त हुवे।

प्रधानमंत्री और कृषिमंत्री के भाषण एवं विशेष संदेश इसी अंक में अन्यत्र दिये है।

सरकार और जनता मिलकर गोवंश का बचावे

गाय के दूध के बिना हमारा और हमारे बच्चों का चलेगा नहीं। और बैल के बिना खेती नहीं हो सकती। इसलिये गाय-बैल, दोनों को भारतीयों ने अपने परिवार का सदस्य माना। यह देखकर समाजशास्त्री, धर्मकारों ने आज्ञा दी कि गाय अवध्य है। याने गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिये। गाय की हत्या के पाप से हम बचें इतना ही संकुचित और अंधा आदर्श सामने रखनेवालों का रास्ता आसान है। लेकिन अगर गोवंश को सफलतापूर्वक बचाना हो, तो गोवंश की सेवा लेने का और उसकी सेवा करने का सच्चा तरीका क्या है, इसका व्यावहारिक निर्णय पूरे अध्ययन के बाद हमें करना होगा।

गोरक्षा का सवाल राष्ट्रीय है, सरकारी है। सरकार के प्रतिनिधियों को इसे हल करना चाहिये। गोहत्या हुई तो उसके लिये सरकार जिम्मेवार होगी और गोरक्षा का सिद्धान्त राष्ट्रमान्य हुआ तो उसका पालन भी सरकार को ही करना होगा।

आज की परिस्थिति में सरकार और जनता मिलकर गोवंश को बचाने के लिये विचार करेंगे ऐसी मुझे आशा है। इस सम्मेलन को मेरी शुभकामनाएं हैं।

नई दिल्ली — काका कालेलकर

३१ अगस्त ७७

गोवध बंदी का समर्थन

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दिल्ली में आगामी ३१ अगस्त को गोसेवा संमेलन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री. सुरजित सिंह बरनाला की अध्यक्षता में होने जा रहा है और उसका उद्घाटन प्रधान मंत्री श्री. मोरारजीभाई देसाई करनेवाले हैं। कृषि से गोसेवा का अभिन्न संबंध है। भारत की आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि में उसका विशेष महत्व है। इसी दृष्टि से मैंने गोसेवा के कार्यक्रमों का तथा गोवध बंदी के विचार का समर्थन किया है।

मुझे आशा है कि गोसेवा सम्मेलन इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करेगा और उपयोगी निष्कर्ष पर पहुंचेगा।

मैं संमेलन की हृदय से सफलता चाहता हूं।

कदमकुआ पटना ३

१८ अगस्त ७७ — जयप्रकाश नारायण

अखिल भारत गोसेवा संमेलन द्वारा पारित प्रस्ताव

ता. ३१ अगस्त और १ सितंबर को दिल्ली में संपन्न हुवे गोसेवा संमेलन में पारित किये गये प्रस्ताव नीचे दिये है। इनमें से (१) गोवंश हत्याबंदी (२) वचनपूर्ति (३) गाय की वरीयता (४) दूध के भावों में गाय का शोषण बंद हो, भैंस के दूधके बराबर भाव मिलें (५) भूमि सीलिंग ऐक्ट से गोशालाओं कि भूमि मुक्त रखी जाय (६) गोबर गॅस प्लँट और गोसेवा संस्थाओं को आयकरमुक्ति आदि प्रस्तावों का सार दसवे अंक में प्रधान मंत्रीसे भेंट इस लेख में छपा गया है। अन्य प्रस्ताव नीचे दिये है –

गोवा में यांत्रिक कसाईखाने की योजना रद्द हो:

इस सम्मेलन को यह जानकर बडा खेद है कि समग्र देश में गोहत्याबन्दी के लिये किये जा रहे आन्दोलन के बावजूद गोवा में केन्द्रीय सरकार की अनुमति से विशाल यांत्रिक कसाईखानों का निर्माण किया जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि इन कसाईखानों में महाराष्ट्र और कर्नाटक के गोवंश की हत्या होगी, जहां गोहत्याबंदी कानून बन चुके हैं। अतः सम्मेलन केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि गोवा में कसाईखानों के निर्माण की योजना को रद्द कर दिया जाय ताकि गोहत्याबंदी का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

गोशाला पिंजरापोलों की करमुक्ति:

अत: यह सम्मेलन सरकार से अनुरोध करता है कि:–

१. इन संस्थाओं को लेब्र, दुकान तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले करों से मुक्त किया जाय।

२. इन संस्थाओं को चैरिटी कमिश्नर अथवा पब्लिक ट्रस्ट ऐक्ट या इसके अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी को दिये जाने वाले शुल्क से मुक्त किया जाय।

३. राज्यों के पशुपालन विभागों द्वारा गोशाला कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाये, जहां उन्हें पशुपालन, पशुचिकित्सा, हरा चारा उत्पादन आदि का प्रशिक्षण दिया जाय ताकि इन संस्थाओं को अपना कार्य चलाने के लिए उच्च वेतन भोगी कर्मचारी न रखने पड़ें।

गोवंश की निकासी पर रोक :

बंगाल, केरल, गोवा ऐसे प्रदेश जहां गोवध बंदी कानून अभी तक नही बना है उन प्रदेशों में भारत के किसी प्रदेश से गोधन नही जाना चाहिए। जो प्रदेश गाय के रक्षण की हमी न लें उस प्रदेश को शेष भारत से गायें मंगवाने का कोई अधिकार नही हो सकता।

सरकारी डेअरियों में गोदुग्ध की उपलब्धि:

गाय का दूध चाहनेवालों कों नगरों में गोदूध उपलब्ध होना आवश्यक है। यह संमेलन शासन से अनुरोध करता है कि सरकारी तथा अन्य डेअरियों में शुद्ध गोदूध पृथक से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। इससे जहां गोदुग्ध का प्रसार वढेगा, वहां गोपालन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

संमेलन में मंत्री का निवेदन

आदरणीय मोरारजीभाई, अध्यक्षजी, वुजुर्गों, वहनों तथा भाइयों ।

गोसेवा के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है और क्या होना है, इसकी जानकारी संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आगे किस दिशा में वढना है इसपर आप विचार कर सके ।

(१) संविधान की धारा ४८ के अनुसार गोवधबंदी

आचार्य विनोबाजी को भारत सरकार ने गत वर्ष वचन दिया था कि सारे भारत में संविधान की धारा ४८ के अनुसार गोवधबंदी कानून वन जावेंगे । केरल और प. बंगाल के कानून ११ सितंवर १९७७ तक वन जाने की बात थी ।

केरल : श्री. रामकृष्ण पाटील, जो प्लॅनिंग कमीशन मेंवर एवं सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष थे, दो वार केरल जाकर आये । केरल में ख्रिश्चन धर्मगुरुओं का विरोध होगा ऐसी कल्पना थी । प्रत्यक्ष मिलने पर ख्रिश्चन धर्मगुरुओं ने पू. विनोबाजी को लिखित में दिया कि गोवधबंदी कानून के लिए उनकी ओर से कोई विरोध नहीं होगा । मुस्लीम लीगवालों से भी मिले । वे भी विरोध नहीं करेंगे ऐसा आभास मिला । कॉंग्रेस संसदीय पक्ष के नेता श्री. यशवंतराव चव्हाण ने और कॉंग्रेस – अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी, दोनों ने केरल सरकार को गोवधबदी कानून ११ सितंवर १९७७ तक बनाने की सिफारिश की है । केरल सरकार ने कहा है कि थोडे समय में ही वे विचार करके लिखेंगे कि गोवधबंदी कानून के संवंध में कहां तक वढ सकते हें ।

गोवा : गोवा की मुख्यमंत्री श्रीमती शशिकला काकोडकर से श्री. रामकृष्ण पाटील मिले। उन्होंने कहा कि यहां के ख्रिश्चन समाज को राजी करना होगा। श्री. पाटीलसाहब बिशप से मिले। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय समाज की गोवध-बंदी की जो भावना है उसका वे आदर करेंगे एवं गोवधबंदी कानून बने तो वे उसका विरोध नहीं करेंगे। श्री. बिशप की यह राय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई। अब गोवा के संबंध में आगे मिलने-जुलने का काम श्री. रंगनाथ दिवाकर, अध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान करेंगे।

प. बंगाल : प. बंगाल के मुख्यमंत्री श्री. ज्योति बसु से श्री. रामकृष्ण पाटील, श्री. प्रभुदयालजी हिम्मतसिंहका, श्री. बजरंगलालजी लाठ, श्री. क्षितिशराय चौधरी और श्री. राधाकृष्ण बजाज ता. १६ अगस्त १९७७ को कलकता में मिले। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वे गोवधबंदी कानून के अनुकूल नहीं हैं। फिर भी राष्ट्रीय प्रश्न है, अतः सब साथियों से विचार करके वे सरकार की राय लिखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मुस्लीम देशों में गोवधबंदी कानून है इसे वे जानते हैं। जहां तक उपयोगी पशुओं की कतलबंदी का मौजुदा कानून है उस पर पूरी सख्ती के साथ अमल करने की वे कोशिश करेंगें।

कलकत्ते में मौजूदा कानून के अनुसार १४ साल से कम उमर के पशुओं के कतल पर रोक है। इसका सचमुच अमल हो तो ७५ प्रतिशत कतल कम हो सकती है। आज तो अधिकांश पशु ८-१० साल से भी कम उमर के कतल होते हैं। प. बंगाल सरकार से हुई बातचीत की जानकारी पू. जयप्रकाशजी को प्रत्यक्ष मिलकर दे दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री श्री. मोरारजी भाई को भी

जानकारी दे दी गई है। गृहमंत्री श्री. चौधरी चरणसिहजी मिलेंगे। तब उन्हें भी जानकारी दे दी जायेगी।

दिल्ली : दिल्ली आने पर मालूम हुआ कि दिल्ली प्रशासन ने गोवधबंदी कानून बनाया था। लेकिन उसे केंद्र की स्वीकृति मिलना बाकी है। पिछले गृहमंत्री के ऐलान में तो स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दिल्ली में संपूर्ण गोवधबंदी लागू है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो गफलत रह गई इसे भारत सरकार दूर करेगी और परिपूर्ण गोवधबंदी कानून दिल्ली में तुरंत लागू किया जायेगा।

(२) संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी

आज के कानून में गाय एवं बछडे-बछडियों को पूरा संरक्षण है। बैल तथा सांडों को बेकाम होने पर कतल करने की छूट है। वास्तव में देखा जाय तो भारतीय संस्कृति में गाय, बैल, नंदी, तीनों के लिए समान आदर की भावना है और तीनों ही देश के लिए समान उपयोगी हैं। अतः यह आवश्यक है कि नंदी-बैल सहित पूरे गोवंश की हत्या बंद हो। इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करना होगा। श्री. मोरारजीभाई संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी के लिए अनुकूल हैं। लेकिन वे चाहते हैं कि इस तरह का कानून बने उसके पहले सारे देश में दो बातों का होना आवश्यक है।

पहली बात बूढी बेकार गायों को संभालने के लिए गोशालाएं एवं गोसदनों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि गायें सडकों पर या खेतों में भटकती न फिरें एवं भूख से तडप-कर न मरें। यह व्यवस्था सरकार और जनता दोनों मिलकर ही कर सकते हैं।

दूसरी बात यह कि लोगों को अपने घरों में गाय के ही घी, दूध के इस्तेमाल का आग्रह रखना चाहिए। हम दूध भैंस का पीते रहेंगे और गाय को बचाना चाहेंगे, यह कभी भी संभवनीय नहीं है।

(३) नसल सुधार

गोवधबंदी कानून होने पर भी यह आवश्यक है कि गाय अर्थशास्त्र में स्वावलंबी बनें। गाय जब तक अपने पैरों पर खडी नहीं होगी किसी भी हालत में बचाई नहीं जा सकती। गाय को स्वावलंबी होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका दूध-उत्पादन बढे और उसके दूध-उत्पादन को पूरी कीमत मिले। आज नसल सुधार के जो प्रयोग चले हैं उनमें दूध बढाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन बैलशक्ति की ओर कतई ध्यान नहीं दिया जाता, यह स्थिति भयानक है। क्रास ब्रीडिंग के बछडों को किसान खरीदना नहीं चाहते। भारत कृषिप्रधान देश है। भारत की सारी खेती ट्रैक्टर से कर लेंगे यह केवल सपना है। मुश्किल से १० प्रतिशत खेती ट्रैक्टर से होती होगी। बैलों की अत्यत आवश्यकता है। बैलशक्ति बढाने पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री और कृषिमंत्री दोनों इस विचार से पूरे सहमत होंगे कि बैलशक्ति कायम रखनी चाहिए, इतना ही नहीं बल्कि बढानी चाहिए। फिर भी इस दिशा में भारत सरकार को प्रत्यक्ष कदम उठाने होंगे। केवल सदिच्छा से काम बनेगा नहीं। यह विषय प्रदेशों का होनेपर भी भारत सरकार को मार्गदर्शन की पूरी जिम्मेदारी है उसे सक्रिय हा॰ र निभाना चाहिए।

भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान उरुलीकांचन वाले नसल सुधार के ।वष । में अभूनपूर्व प्रयोग कर रहे हैं। दस लाख गायों

की नसल सुधार की उनकी योजना है। महाराष्ट्र सरकार, श्री अरविंद मफतलाल और श्री मणिभाई देसाई, ये तीनों इस योजना के प्राण हैं। इनके सचालक मंडल को यह बात स्वीकार है कि बैलशक्ति कम न होने दी जाय, वल्कि बढाई जाय। उनकी सदिच्छा के लिए हम कृतज्ञ हैं। लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष में कहीं भी यह नहीं देखा जा सका कि बैलशक्ति कायम रही हो या बढी हो। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि वे अपने लक्ष्य पर कायम रहेंगे और बैलशक्ति दिन-प्रतिदिन बढाने की कोशिश करेंगे।

(४) गोदूध को उचित कीमत

गाय को अपने पैरों पर खडी करने के लिए उसका दूध-उत्पादन बढाना आवश्यक है ही। लेकिन साथ-साथ दूध के उत्पादन को उचित कीमत मिलना भी आवश्यक है। वरना सारा उत्पादन बढाना व्यर्थ सिद्ध होगा। पिछले ३०-४० वर्षों से अधिक चिकनाई का दूध चाहनेवाले व्यापारियों ने भैंस के दूध को बढावा दिया है। गाय के दूध के मुकाबले भैंस के दूध को ५० प्रतिशत अधिक याने डचोढे भाव दिये गये हैं। इसलिए जहां भी डेरियां बनी, चाहे वे सरकारी हों, सहकारी हों, या निजी हों, हर जगह गोदूध को कम कीमत देने के कारण ग्वालों के लिए गायों का पालन असंभव होता गया। दुख की बात है कि आज गाय के प्रति यह अन्याय बरावर चालू है। इस अन्याय को दूर किये बिना किसी भी हालत में गाय पनप नहीं सकती।

महाराष्ट्र सरकार ने यह महसूस किया कि गोदूध को पूरी कीमत दिये बिना गोसंवर्धन संभव नहीं। अतः उन्होंने थोडा घाटा उठाकर भी गोदूध को भैंस के दूध के वरावर भाव देना तय किया है। पिछले ३-४ साल से यह प्रयोग चालू है। उसका

परिणाम यह हुआ है कि महाराष्ट्र में गायें बढने लगी हैं। समान भाव देने में एक खतरा है, जिसके लिए सावधानी रखना आवश्यक है। खतरा यह है कि भैंस के दूध में पानी मिलाकर उसे गाय के नाम से बेचा जायेगा। भैंसवाले को और भी ज्यादा दाम मिलेंगे। याने गाय के नाम पर भैंस ही आगे बढेगी। इस खतरे को टालने के लिए कई तरह की टेस्ट ढूंढी जा रही हैं। मैं एक ही सुझाव देना चाहूंगा कि गोदूध के पूरे भाव उन्हीं ग्वालों को दिये जायं जो ग्वाले केवल गाय ही रखें, भैंस न रखें।

(५) पशु-खाद्य का निर्यात बंद हो

गोसेवा के लिए आवश्यक है कि हमारे पशु खाद्य जिनका देश में उपयोग हो सके उन्हें विदेशों में न भेजा जाय। हमारे प्रधानमंत्रीजी ने इसके लिए पूरी अनुकूलता बताई है। कृषि मंत्री एवं कृषि मंत्रालय भी यह चाहता है कि पशुखाद्य बाहर न भेजें जाय लेकिन पशु मंत्रालय में उत्पादन का एक भाग है उनका कहना है कि विदेशों में खली भेजेंगे तो तिलहन के उत्पादकों को अधिक कीमत मिलेगी और वे अधिक उत्पादन बढावेंगे। आजतक हमें कहा जाता था कि वाणिज्य मंत्रालय खली बाहर भेजता है। वाणिज्य मंत्री श्री धारियाजी से मिलने पर उन्होंने बताया कि पशुखाद्यों को निर्यात करने का उनका कोई आग्रह नहीं है। कृषि मंत्रालय कहेगा वैसा करने की उनकी तैयारी है।

(६) गोसेवा संस्थाओं को इन्कम टैक्स से मुक्ति

गोसेवा का काम राष्ट्र का बुनियादी काम है। जो संस्थाएं केवल गोसेवा के उद्देश्य से चलती हैं, ऐसी गोसेवा की समस्त

संस्थाओं को, खास तौर से गोसेवा संघटन, गोशाला, पिंजरापोल, गोसंवर्धन, रिसर्च आदि के लिए चलनेवाली संस्थाओं की तरह दान देनेवाले दाताओं व उद्योगों को सेक्शन ३५ के अंतर्गत इन्कम टैक्स को शतप्रतिशत छुट दी जानी चाहिए। इन्कम टैक्स की इस विशेष छुट से दाताओं को दान देने को प्रोत्साहन रहेगा, उससे गोसेवा के काम आगे बढेंगे, एवं देश लाभान्वित होगा।

(७) दिल्ली दूध योजना में शुद्ध गोदूध अलग से मिले

हमारे प्रधानमंत्री तथा सघ चाहता है कि घर-घर में गाय के दूध का इस्तेमाल बढे। लोग गोदूध का संकल्प लें। अतः दिल्ली दूध योजना में तथा मदर डेयरी में शुद्ध गोदूध अलग से मिल सके ऐसी व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है।

(८) सत्तासंपन्न केंद्रीय संगठन

गोरक्षण, गोसंवर्धन का कार्य सरकार व जनता द्वारा मिल-जुल कर होगा। अतः सरकारी, बिनसरकारी गोसेवकों का मिलाजुला ऐसा एक संगठन होना चाहिए, जो गोसेवा की नीति के बारे में निर्णय कर सकें एवं जिसके निर्णय को साधारण तौर पर मंत्रालय मानेगा ऐसी मान्यता होनी चाहिए।

दिल्ली — राधाकृष्ण बजाज

ता. ३१-८-७७ — महामंत्री

अ. भा. कृषि गोसेवा संघ गोसेवा संमेलन, दिल्ली

प्रधानमंत्री श्री. मोरारजी देसाई का भाषण

३१ अगस्त १९७७

अध्यक्ष महोदय, वहनों और भाइयों,

इस देश में गोहत्या बंद हो, गोवंश की हत्या बंद हो, इस बारे में ज्यादातर लोगों का मत साफ है कि गोहत्या बद होनी चाहिए। उसके लिये आंदोलन चले, अनेक भाई-बहनों ने कष्ट भी उठाये हैं। हमारे संविधान में इसके लिए डायरेक्टिव भी दिया गया है। मैं खुद तो मानता हूं कि किसी भी प्राणी की हत्या न हो। मनुष्य सबसे ऊंचा प्राणी है ऐसा उसका दावा है। वह अन्य सब जीवों की हत्या करेगा तो उसे ऊंचा कौन मानेगा ? वह तो कातिल कहा जायेगा। मगर ऐसो मान्यता सब लागों की नहीं है। इस देश में और सारी दुनिया में ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं। मैं उनके साथ चर्चा में नहीं पडना चाहता। मैं तमाम कतलखाने वंद करने जाऊं तो लोकतंत्र में बहुमत का निर्णय मानना होता है। बहुमती ऐसा निर्णय करे कि सबको मांसाहार करना चाहिए तो मैं क्या करूं? इसलिए जल्दबाजी में कदम नहीं उठाये जा सकते। लोगों के पास जाकर समझाना चाहिये। मैं खुद तो ऐसी औषधी भी नहीं लेता जिसमें किसी प्राणी का नाश होता हो, न ऐसे इंजेक्शन लेता हूं, न वेक्सीनेशन करवाता हूं। मृत्यु आवे तो भी ऐसी औषधि नहीं लेना चाहूंगा।

मैं चाहता हूं कि गोवंश की हत्या न हो, क्योंकि गाय का संबंध खेती से बहुत जुडा है, गाय एक निर्दोष प्राणी है, समाज-पर उपकार करती है। हिंदुओं ने गोमूत्र को भी पवित्र माना है, उसमें कोडे नहीं पडते। हमारा देश हर दिशा में पिछडता गया इस कारण गाय की उपेक्षा हुई। गाय कम दूध देती है, क्योंकि उसका ठीक से संवर्धन नहीं हुआ। आज देश में आपरेशन फ्लड योजना की बातें चली हैं। सौभाग्य से इस योजना में केवल गोसंवर्धन ही आता है, क्योंकि भैंस की नसल बदली नहीं जा सकती। गाय में जितना चाहें दूध बढाया जा सकता है। इसलिये आपरेशन फ्लड योजना में तो गोसंवर्धन पर ही जोर देना आवश्यक हो गया है।

दिल्ली में गाय, भैंस, दोनों दूध आते हैं। लोग चाहते हैं कि गाय का शुद्ध दूध अलग से मिले। मैंने कृषि मंत्रीजी से कहा है कि दोनों दूध अलग से बेचने चाहिए। गाय का दूध अलग से मिलने लगेगा तो दिल्लीवालों की कोई मुसीबत नहीं रहेगी। दिल्लीवाले खुद गाय की डेरियां क्यों नहीं चलाते? दिल्लीवालों को गोसंवर्धन के लिए खुद मिहनत करनी चाहिए। मैं बार-बार कहता हूं कि जो लोग गोरक्षा में मानते हैं उन लोगों को अपने घरों में कम से कम गाय का ही दूध पीना चाहिए। इसका निश्चय करना चाहिये। यहां जो लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग गोदूध ही पीते होंगे मैं नहीं जानता। हम लोग बातें गोरक्षा की करें और दूध गाय का न पीकर भैंस का पीयें तो गो-संवर्धन कैसे होगा? हमें तो अधिक पैसे देकर भी गोदूध पीना चाहिए। तभी गोदूध की पूरी कीमत होगी। श्री. राधाकृष्णजी

ने बताया कि आजकल डेरियों में दूध की खरीदी में भैंस के मुकाबले गोदूध को ४० प्रतिशत कीमत कम दी जाती है। इतना बड़ा फरक रखना तो न्याय नहीं है, इसमें मुझे कोई शक नहीं।

गोवधबंदी का प्रश्न आता है तब ख्रिश्चनों का और मुसलमानों का नाम लिया जाता है कि इन लोगों का गोवधबंदी के लिए विरोध होगा, यह बराबर नहीं है। मुगलों के जमाने के पहले से ही इस देश में गोवध बंदी चली आ रही है। अंग्रेजों के जमाने में ही गोवध चला और तब से गाय दुर्बल बनती गई। हम उसकी रक्षा नहीं कर सके, और न संवर्धन कर सके। आप कहेंगे कि बूढी गायों की रक्षा राज्य करे तो यह मुश्किल होगा। हम बूढे मनुष्यों के लिये भी व्यवस्था नहीं कर सकते तो उनसे पहले बूढे पशुओं की रक्षा कैसे करें यह देखना चाहिये। जो लोग गोरक्षा में मानते हैं वे सब मिलकर विचार करें। बूढी गायों की रक्षा के संबंध में मेरा काई विरोध नहीं हो सकता। लेकिन यह काम केवल सरकार के भरोसे या केवल जोशीली बातें करने से नहीं होगा। जनता के विचार मजबूत बनाने होंगे और उसके अनुसार आचार भी करना होगा। श्री. राधाकृष्णजी की यह मांग कि गोसेवा संस्थाओं को आयकर में पूरी छूट दी जाय, यह बात बराबर है। आयकर से गोसेवा संस्थाओं को पूरी छूट मिलनी चाहिये।

यह भी सोचना चाहिए कि गाय बूढी होती है, दूध नहीं देती है तो उसे बेचते क्यों है? जो गाय बेचते हैं वे भी कतल के लिये जिम्मेवार हैं। जीवनभर जिसकी सेवा ली उसे बेचें

क्यों ? खुद ही उसका पोषण क्यों न करें ? इस प्रकार सोचने के बजाय लोग कानून बनाने की ही बात करते हैं। हम अपना कर्तव्य निभायें तो कानून बनाना भी आसान होगा। केंद्रीय कानून भी बनाया जा सकता है. लेकिन उसका पालन तो प्रदेशवालों को ही करना होगा। इसलिये यही होना चाहिये कि प्रदेशवालों को कानून बनाने के लिये समझाया जाय। वे लोग समझने पर नहीं मानेंगे ऐसा मैं नहीं मानता। बंगाल, केरल और गोवा तीन प्रदेश बचे है। मैं आशा करता हूं कि ये प्रदेश भी मान जायेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि केवल आप लोग ही समझायें। समझाने में मैं भी हिस्सा लूंगा।

मैं तो नागालैंड और मेघालय को भी समझाने वाला हूं जहां इसके विपरीत बहुत बडी हवा है। वे भी समझ सकते हैं। आखिर हरेक की एक संस्कृति है। और यह संस्कृति भी आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। इस संस्कृति को अधिकांश लोग मानते आये हैं, उस संस्कृति का पालन करना सब लोगों का कर्तव्य हो जाता है। जो थोडे लोग रह जाते है उनको सब लोगों का साथ देना चाहिये, उसके प्रतिकूल कुछ नहीं करना चाहिये। मगर यह सारी हवा हमें पैदा करनी है, तब यह देश जैसा बनना चाहिये, वैसा बनेगा। मुझे पूरा विश्वास . और पूरी श्रद्धा है कि थोडे वर्षों में हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा यह देश बनकर रहेगा।

मुझसे जो बन पडेगा, करता रहूंगा। अगर आप लोग मुझे ही करने को कहते रहोगे तो आपकी शक्ति बढेगी नहीं। आपकी शक्ति ही मेरी शक्ति है,मेरे पास अन्य कोई शक्ति नहीं।

आप लोग प्रयत्न करें। मुझसे जो मदद चाहे लेते रहें, मैं मदद अवश्य देता रहूंगा। इस संमेलन का उद्घाटन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने संमेलन में बुलाया, आपका ऋणी हूं। आपके प्रयत्नों को अधिक बल मिले, सही तरीके से काम हो ऐसी आशा करता हुआ संमेलन की सफलता चाहता हूं। सबको धन्यवाद।

गोमाता हमारी संस्कृति की प्रतीक

गौमाता हमारी संस्कृति की प्रतीक है। उसके सौम्य स्वरूप में भारतीय संस्कृति को सौम्यता, अहिंसा, सुंदरता, समृद्धि और उत्कृष्टता झलकती है। गौ प्राचीन काल से हमारी आर्थिक व्यवस्था की धुरी रही हैं। आज विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसका लाभ उठा कर गौ वंश की समृद्धि और उसका लालन पालन और भी अधिक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें जो दूध और दूध से बने पदार्थ मिलेंगे उससे देश में कुपोषण दूर होगा और लोग स्वस्थ और सुंदर बनेंगे।

आशा है आपका सम्मेलन इस दृष्टि से लोगों में नई जागृति पैदा करेगा, उन्हें गौ वंश समृद्धि के लिए उद्यत करेगा।

मैं आपके प्रयास की सफलता की कामना करता हूं।

केदारनाथ साहनी
मुख्य कार्यकारी पार्षद दिल्ली

गीर और क्रॉसब्रेड का अध्ययन

(कस्तूरबा कृषिक्षेत्र इंदौर)

कस्तूरबाग्राम कृषि क्षेत्र में गोसंवर्धन पर हम अपनी गौशाला में विगत २० वर्षो से वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोग तथा परीक्षण कर रहे है। इन प्रयोग और परीक्षणों द्वारा हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की दृष्टि से किस नस्ल की गाय हमारे देश की परिस्थिति में उपयुक्त रहेगी।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है देश की लगभग सत्तर प्रतिशत आवादीं इस कार्य में लगी हुई है। आधुनिक यंत्र-चलित कृषि उपकरणों से हमारे यहां की पूरी खेती होना संभव नहीं है। खेतों का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होते जा रहा है। अत: छोटे किसान इन मशीनों को खरीद भी नही सकेंगे। और न इनका उपयोग करने हेतु इनके पास इतनी भूमि ही है, इसलिए हमें हमारे देश की परिस्थिति के अनुरूप गाय की खोज करना है जो सर्वागीण हो अर्थात जिसके बछडे भी खेती में काम कर सकें और वछडियों से अधिक दूध भी मिल सके।

किसानों की दृष्टि से एक औसत गाय का अभिप्राय है

१. गाय की दूध देने की क्षमता १० से १५ लीटर हो और जो किसानों के यहां १० लीटर दूध दे सके।

२. गाय ऐसी हो जिसको किसान आसानी से पाल सके. स्थानिक चारे दाने पर।

३. उसके बैल कृषि कार्य के लिए किसी भी मौसम मे उपयुक्त हों।

४. अरली मेच्युरिटी हो तीन वर्ष में पहिला वच्चा दे सके।

५. ड्राय पीरियेड तीन माह से अधिक न हो।

६. बोमारियां जिनमें कम आती हो।

७. एक ब्यात अर्थात ३०० दिन में २,००० लीटर तक दूध देने की क्षमता हो।

कस्तूरवाग्राम की गौशाला में हमने देशी तथा विदेशी दोनो नस्लो के जानवरों को रखकर प्रजनन, संकरण, आहार आदि के प्रयोग मुख्य रूप

से कांकरेज, मालवी, गीर एवं रेड्डेन, जरसी, होस्टीन फ्रीजियन आदि नस्लों के जानवरों पर किये।

क्रॉस ब्रीडिंग

विदेशी नस्लों में उचित देखभाल तथा संतुलित आहार के माध्यम से गायों के दूध में आशाजनक सफलता मिली। दैनिक सताईस लीटर दूध उत्पादन तक हम पहुंच गये थे। क्रासब्रेड के परिणाम भी आहार, पोषण एवं उचित डाक्टरी सेवा के द्वारा हमारे यहां काफी आशाजनक रहे। जहां तक क्रॉसब्रीड जानवरों का प्रश्न है, यदि इनकी उचित देखभाल, आहार, पोषण, उपचार आदि की वैज्ञानिक व्यवस्था रही तो दूध की दृष्टि से ये जानवर लाभदायी है। किन्तु यदि आहार, पोषण और बीमारी का ठीक से इलाज नहीं हुआ तो न जानवरों से दूध मिल सकेगा और न जानवर ही बच पायेगा।

क्रॉस ब्रीडिंग एवं अपग्रेड ब्रीडिंग पर भी हमने प्रयोग परिक्षण किये। गीर-जरसी गीर-मालवी को एक दूसरे से क्रॉस किया और भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में रखकर देखा एवं सिलेक्टेड ब्रीडिंग के प्रयोग भी किये गये।

सिलेक्टेड ब्रीडिंग

उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संकर नस्ल की गायों की अपेक्षा देशी नस्ल की गाय अपने देश की दृष्टि से पालना अधिक आसान एवं लाभदायक है। देशी नस्ल की गाय में यदि अपग्रेड ब्रीडिंग किया जाय तो विदेशी नस्ल की गायो की तरह ही हमें दूध मिल सकता है। देशी नस्ल की गाय गीर में दूध देने की क्षमता काफी अच्छी है एव इसके बछडे अच्छे बैल बनते है। वजन खीचने एवं कृषि कार्य के लिए किसी भी मौसम में इनसे काम लिया जा सकता है।

विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर गीर नस्ल की गायों में सिलेक्टेड ब्रिडींगसे हमें निम्न लिखित स्तर तक सफलता मिली है।

१. गीर नस्ल की गाय का औसत दूध ३३१ दिन का ३६९४ लीटर रहा।
२. मेच्युरिटी -- १६ से १९ माह में आ जाती है।
३. ड्राय पीरीयेड -- ६० दिन रखना पडता है।

४. इनमें बीमारियां बहुत कम आती हैं एवं इनमें बीमारी सहन करने की शक्ति अधिक है।

५. इस नस्ल के बैल मजबूत तथा अधिक वजन खींच सकने की क्षमता रखते है।

६. मौसम और जलवायु का इनके स्वास्थ, कार्यक्षमता एवं दूध पर कोई विशेष असर नहीं पडता।

७. इन्हें खेतों में चरने हेतु छोडा जा सकता है।

गीर और क्रॉस ब्रेड का तुलनात्मक अध्ययन

१ दूधः— गीर का औसतन दूध ३३१ दिन में ३६९४ लीटर रहा तथा क्रॉसब्रेड का औसत दूध ३६५ दिन में ४००९ लीटर रहा।

गीर गाय को चरने हेतु बाहर छोडा जा सकता है और इसके दूध तथा तन्दुरूस्ती में अधिक अंतर नहीं आता. जब कि क्रासब्रेड को चरने हेतु यदि बाहर छोडा गया तो इनका दूध बहुत कम हो जाता है, तथा तन्दुरूस्ती एकदम खराब हो जाती है।

२ आहार :— गीर गाय के आहार को सामान्य रूप से बदला जा सकता है, अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आवश्यकता नहीं रहती है यद्यपि संतुलित आहार नहीं दिया गया तो इनके दूध पर मामूली प्रभाव पडता है।

जब की क्रॉसब्रेड जानवर को वैज्ञानिक ढंग से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, यदि इन्हें संतुलित आहार नहीं मिला तो इनके स्वास्थ तथा दूध में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है।

३ मौसम एवं जलवायु का प्रभावः— गीर नस्ल की गायों पर मौसम और जलवायु का विशेष प्रभाव नहीं पडता।

जब की क्रॉसब्रेड नस्ल की गायों पर मौसम और जलवायु का बहुत असर होता है। इससे इनके दूध उत्पादन में यदि मौसम के अनुसार परिवर्तन नहीं किया तो बहुत अंतर होता है।

४ बीमारियांः— गीर नस्ल की गायों में रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक है तथा इनके रोग का आभाप हमें आसानी से हो जाता है

सामान्यत: यदि कोई रोग इन्हें आता है तो ये खाना बंद कर देती है तथा रोग एकाएक नहीं बढता इससे इनका उपचार करना आसान रहता है। इन्हें दूसरे जानवरों से रोग बहुत जल्दी नहीं लगते।

जबकि क्रॉसब्रेड जानवरों में रोग एकाएक आता है यदि तुरन्त उपचार संभव न हुआ तो इन्हें बचाना संभव नहीं है। बीमार पशु खाना बंद नहीं करते तथा कौनसा रोग इन्हें है समझ पाना सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं हैं। इन्हें दूसरे जानवरों के रोग भी बहुत जल्दी लगते हैं।

५ व्यवस्था:- गीर नस्ल की गाय को सामान्यत: हम अपनी गौशाला में जो किसानों के यहां रहती है उसमें पाल सकते है।

जबकि क्रॉसब्रेड जानवरों के लिए व्यवस्थित गौशाला चाहिए अन्यथा इन्हें नहीं पाला जा सकता।

६ मेच्युरिटी:- गीर गाय की बछडियां आमतौर पर तीन से साडे-तीन वर्ष में पहिला बच्चा दे देती है।

क्रॉसब्रेड गाय की बछडियां आमतौर पर तीस माह में पहिला बच्चा देती है।

७ सूखेदिन:- गीर गाय का ड्राय पीरियड साठ दिन रहता है। आमतौर पर यदि आहार-पोषण आदि ठीक रहा तो इन्हें साठ दिन के लिए सूखा रखना ही होता है अन्यथा ये अगला बच्चा देने तक दूध देते रहती है।

क्रॉसब्रेड जानवरों का ड्राय पीरियड भी साठ दिन है यदि देखभाल आदि ठीक रही तो इन्हें साठ दिन के लिए सूखा रखना होता है। अन्यथा ये अगला बच्चा होने तक दूध देती रहती है।

८ बैलो की शक्ति :- गीर नस्ल के बछडे अच्छे बैल बनते है, कृषि कार्य के लिए ये उपयुक्त पाये गये है। वजन खींचने में भी ये अन्य देशी बैलों की अपेक्षा काफी मजबूत हैं। बाजारमें आसानी से बिक जाते है।

क्रॉसब्रेड जानवरों के बैलों पर मौसम का बहुत असर होता है। गरमी के दिनों में इनकी कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है एवं इनसे अधिक वजन नहीं खींचा जा सकता।

९ अन्यबातें :- गीर नस्ल की गायों में अपने बच्चों के प्रति ममता

रहती है यदि गाय का बछडा मर जाय या बिना बछडे के दूध नहीं निकाला जा सकता और यदि निकालने के लिये प्रयत्न किया गया तो बहुत समय लगता है। तथा दूध जाता है।

क्रॉसब्रेड गाय में अपने बच्चों के प्रति कोई ममता नहीं होती। इन्हें अपने बछडों से कोई वास्ता नहीं। ये बिना बछडे के भी दूध दे सकती है बछडा मर जाय तो भी ये दूध देना बंद नहीं करती तथा बछडों के अभाव में इनका दूध नहीं सूखता। इनके बछडों को बाजार में कोई खरीदता नहीं है अत: बिक्री की समस्या बनी रहती है।

इस लेख में जो अनुभव आदि हमें प्रयोग के आधार पर ज्ञात हुए है उन पर ही हमने प्रकाश डाला है। अभी गीर नस्ल पर हमारे सिलेक्टेड ब्रीडिंग आदि के प्रयोग चल रहे हैं इनका परिणाम आगे चलकर ज्ञात होगा कि हम इस नस्ल के संवर्धन में कितने सफल होते है।

इंदौर
२५-६-७७

गोविंद कुटी मेनन
संचालक

• संदेश •

गोपालन का न केवल भारत की संस्कृति में विशिष्ट स्थान हें अपितु देश की अर्थव्यवस्था में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। देश में स्वेत-क्रांति को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक तरीकोंसे गो-नस्ल में सुधार किया जावे और इनमें बीमारियों की रोकथाम की समुचित व्यवस्था हो।

सम्मेलन की सफलता के लिए मैं अपनी शुभ कामनाएं भेजता हूं।

– रघुकुल तिलक
राज्यपाल, राजस्थान

MOTHER COW

Mother cow is in many ways better than the mother who gave us birth. Our mother gives us milk for a couple of years and then expects us fto serve her when we grew up. Mother cow expects from us nothing but grass and grain. Our mother often falls ill and expects service rom us. Mother cow rarely falls ill. Hers is an unbroken record of service which does not end with her death. Our mother when she dies means expenses of burial of cremation. Mother cow is as useful dead as when she is alive. We can make use of every part of her body – her flesh, her bones, her intestines, her horns and her skin. Well, I say this not to disparage the mother who gives us birth, but in order to show you the substantial reasons for my worshipping the cow.

Mahatma Gandhi

Harijan
15-9-40

ADDRESS BY SARDAR SURJIT SINGH BARNALA UNION MINISTER OF AGRICULTURE & IRRIGATION IN GOSEWA CONFERENCE, DELHI

Friends,

I am grateful for the honour extended to me by the Akhil Bharat Krishi Go Sewa Sangh in inviting me to preside over the Conference.

The cow has occupied for thousands of years such an important place in the economy of the country that it has become an object of worship. The cow provided through milk almost the main source of animal protein and nourishment for the people and particularly the children. It has been the backbone of our agriculture because of the bullock power it has been providing since ages. A man's wealth was measured by the number of cows that he possessed. Not only has the cow been a most vital factor in the economic life of the country, it has also been cherished as a Mother symbol. It symbolised tolerance, meekness and service. It has always been and will continue to be revered and considered a kingpin of the rural economy in the country. Let no one have any fears about its continued significance in India both in its use as a milch cattle and as a source for draught animal.

The Constitution has in Article 48 enshrined the sentiments of our people, and has directed that the State shall endeavour to "organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and other milch and draught animals". Not only is there restriction on the slaughter of cows and calves and other milch and draught

animals, but the State has been directed to organise "animal husbandry on modern and scientific lines" and "to take steps for preserving and Improving the breeds". Let me assure you earnestly that this shall be the endeavour of the new Government and will be pursued with greater vigour.

Recognising the imporrance of the cow in the rural economy, we shall take up additional programmes to improve the breed and the production of cows, which should help programmes to add to its usefulness, and also raise the incomes of the small farmers and agricultural labourers. Although the responsibility for preservation, protection and improvement of stock is on the States, the Centre has been advising the State Governments in this regard periodically.

Laws relating to cow protection have been in force almost all over the country, except in small marginal pockets where the population is sensitive to this issue. The Central Government have been keeping a watch on the implementation by the State Governments of the laws already in force. It wouid be of interest to you all to know that West Bengal is implementing the West Bengal Animal Slaughters Control Act as had been agreed to last year in August during discussions held between Acharya Vinoba BhaveJi and Shri Mohan Lal Sukhadia. The Kerala Government has extended the legislation which prohibits slaughter of useful animal In Panchayat areas to the Municipal areas also since last year. The Central Government will try to persuade these two States also to fall in line with other States.

To encourage production of cow's milk it has been suggested that cow's milk should be given the same price as buffalo milk. Under the existing price poilicy by which public and cooperative dairies accept milk from primary producers there is no doubt that buffalo milk gets a more favourable price on account of its higher fat content. Maharashtra has tried an experiment of offering uniform

price for buffalo as well as cow's milk. I find, the Sangh has recommended that this should be adopted as a model for the rest of the country also. While there is logic in the argument, some fears have been expressed by others that in practice it may prove self-defeating. Identical prices for buffalo and cow's milk may, in fact, have a reverse effect than what is desired, since it will make diluted buffalo milk a more profitable item for sale than cow's milk and the offtake of buffalo milk may actually rise. I presume, however that the intention clearly is to lay more emphasis on paying a remunerative price for cow's milk. We are requesting the National Dairy Development Board to undertake in consultation with the concerned organisations including the Sangh a detailed analysis of cost of production of milk in different areas and the Prices being obtained by the producers of milk. The Board will on the basis of this study recommend a pricing policy which will ensure to the producer a remunerative price for cow's milk.

Now, I come to another major issue which has been a problem in Indian agriculture, namely, the quality of milch animals and the bullocks. By and large milk production in rural areas was always for family consumption and not for sale. It is only a recent development that milk has become an important commodity for sale from the rural areas. The importance of the cow previously was more as a producer of drought animals which were used for operations on the farm and for transport by the farmer. The Akhil Bharat Krishi Go Sewa Sangh has suggested an improvement in the quality of milch animals and bullocks and has also suggested an improvement of the recognised breeds either by upgrading or selective breeding. This is a very apt suggestion and let me assure you that no one will be happier than me and our Government in taking all measures to improve the breeds, as also to ensure markets for the milk

produced by small farmers and agricultural labourers. We are committed to the policy that cattle and buffalo development should be based on increasing milk produclion with a view to meet the dietary needs of the people in general and also improving the work efficiency of bullocks in rnral areas. The needs of agriculture in the shape of drought animals and milk for consumption of the people has been clearly recognised by Government. Breeding for milk production will be concentrated in the milk shed areas which can feed the dairy plants. Production of milk has per force to be on commercial basis and remuncrative enough for farmers to keep milch animals. Increase in milk production are being attempted through a system of planned cross breeding, selective breeding and upgrading of indigenous cattle, and also selective breeding and upgrading of buffaloes, depending upon the suitability of each system under the present local conditions. Thus, the emphasis given by the Sangh upon upgrading or selective breeding is amply recognised by Government and this aspect of breeding will continue to receive constant attention of the Government.

Another important point relates to improving the drought capacity of bullocks. Though there has been a progressive increase in all classes of cattle, a view held by almost all experts is that there is deterioration in the quality of cattle. The reason for this is attributable to the fact that increasing requirment of cattle for agricultural activity has been met primarily by increase in number rather than through effeoting improvement in productivity or better utilisation of stock. This is a vicious circle and it is a drain on the economy of the farmers particularly with small holdings. The existing stock of working animials, according to the Notional Commission on Agriculture, would be sufficient for meeting the existing needs of the agriculture provided the quality of the animals is improved. Government have

sought to prevent deterioration and to Improve the drought quality of bullocks. Established Indian breeds will be promoted by selective breeding or upgrading.

Steps taken by Government and the encouragement given for installation of Gobar gas plants are well known and need no special mention. The thrust in this programme will be an intensification of the current efforts.

It has been suggested that Gosadans and Goshalas should be given government assistance. The suggestion is well conceived ; As you know, assistance was provided in the Second Five Year plan and was continued in the Third Plan for development of Goshalas under a comprehensive Goshalas Development Scheme. From the Fourth Plan the scheme has been transferred to the State sector. Experience has shown that some Goshalas have made remarkable progress. In addition to Government assistance, voluntary contributions and local enthusiasm will have to play a greater role. The available resources, if suitably harnessed, could enable the institutions to play an effective role in cattle development. We would certainly consider any concrete proposals and suggestions of the Akhil Bharat Krishi Go Sewo Sangh in this connection if these institutions could play a more significant role in breeding, extension activities on animal health and cattle feeding programmes. The magnitude of the problem will have to be assessed, however, before any project can be taken in hand.

As far as special relief in the income tax law far Go Sewa institutions is concerned it appears to me that, this could be considered on merits since these institutions are primarily charitable institutions. I would request the Sangh to take up this matter with my colleague in the Finance Ministry, though you could presume full support from me.

Better breed of cattle, though essential, is not a substitute for better feeding. We have taken steps to evolve good varieties of fodder and balanced feed which could also be economical. A number of central institutes like, Indian Institute of Grassland and Fodder Research, Central Arid Zone Research Institute and National Dairy Research Institute are doing useful work in this direction. We are also adopting a restrictive policy on export of feed and ingredients like oilcakes so that the prices of cattle feed in the domestic markets are kept at a reasonable level and milk production does not become unremunerative to the farmers.

You will be glad to know that we have decided to revive the Go Samwardhan Advisory Council, which will have both officials and non afficials as its members. Among other member, Akhil Bharat Krishi Go sewa Sangh will also be represented on this Council. The Council will review the schemes and advise the central and States Governmentson various aspects of breeding and development of the cattle wealth as also development of Goshalas on proper lines.

I have outlined briefly some of the steps that the Government has been taking to ensure that cow continues to occupy a vital place in the economy of this country and its usefulness can be increased in the years to come. I hope the deliberations of this Conference would bring out many more useful suggestions in the direction. I wish the Conference all success. I am happy to be associated with this Conference and to preside over this morning's function.

31-8-77

विनोबाजी का संदेश कर्म-मुक्ति के पूर्व

१. गोहत्याबंदी-संकल्पपूर्ति के लिए एक साल का समय दिया था। ११ सितंबर १९७७ को एक साल पूरा होगा। इस बीच गोसेवा पर पूरी शक्ति केंद्रित की जाय।

२. गोग्रास योजना के लाखों सदस्य बनें, ऐसी अपेक्षा है। उसके लिए सबको काम में लगना चाहिए।

अ – जितनी गोशालाएं, गोसदन या अन्य गोसेवा संबंधी संस्थाएं है, उनसे संबंधित सभी सज्जनों को गोग्रास-सदस्य बनना चाहिए।

आ – खादी का काम पचास हजार गांवों में है। उन सब गांवों में गोग्रास-सदस्य होने चाहिए। जिस ग्राम में स्थानिक सदस्य न हो, वहां खादी-संस्था स्वयं सदस्य बनें, ताकि, पत्रिका हर गांव में पहुंचती रहे।

इ – गो-प्रेमी एवं गाय की सेवा लेनेवाला हर परिवार सदस्य बनें।

ई – सर्वोदय समाज के सभी सेवक स्वयं गोग्रास-सदस्य बनें एवं घर-घर सदस्य बनावें। ११ सितंबर १९७७ तक का समय और शक्ति गोसेवा कार्य में केंद्रित की जायेगी तो कोई ठोस परिणाम निकल सकेगा।

उ – बहनों के संगठनों को तथा बहनों को विशेष रूप से गोग्रास-सदस्य बनाने का काम करना चाहिए।

३. गोदुग्ध प्रचार – अपने अपने घरों में गाय का दूध अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए सामूहिक संकल्प लिया जाय।

४. गांवों में ग्राम-सभाएं गठित करके उनके द्वारा गोसदन कायम किये जावें। हर गांव में कृषि-गोसेवा, खादी-ग्रामोद्योग, नई-तालीम, व्यसन-मुक्ति और अदालत-मुक्ति सबका संमिलित सहयोग लेकर ग्रामों का उत्थान किया जाये।

२४-१२-१९७६

बाबा की शुभकामना
राम हरि

रजि. नं. WDA – 86 बिना तिकिट परवाना लाइसन्स नं. 8

All the states in India have prohibited the slaughter of cows. The only states left are Bengal, Kerala and Goa. This is not only a useful reform but it is advocated by the vast majority of our population. I would therefore humbly request the three above named governments to fall in line with the rest of India. I have no doubt that the majority of the population in these three states would be in favour of the reform. May I hope that the three governments will fall in line with the rest of India.

Dated : 30. 8. 77 (sd) **J. B. Kripalani**

बुक-पोष्ट

प्रेषक : 'गोग्रास' मासिक पत्रिका,
गोपुरी, वर्धा (महाराष्ट्र) ४४२००१